है कि उचित दर की दुकानों के आवंटन के मामले में सहकारी समितियों को तरजीह दी जाए । लेकिन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संचालन पक्ष की जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है और उचित दर की दुकानों के आवंटन के लिए प्राथमिकताओं के बारे में निर्णय उनके द्वारा किया जाता है ।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सहकारी समितियों द्वारा चलाई जाने वाली उचित दर की दुकानों द्वारा की जाने वाली अनियमितताओं के बारे में आंकड़े इस मंत्रालय में नहीं रखे जाते हैं ।

राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से अनुरोध किया गया है कि वे उचित दर की दुकानों पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं की आपूर्ति तथा उपलब्धता पर कड़ी निगरानी रखें, ताकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं को खुले बाजार में जाने से रोका जा सके । राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन नियमित रूप से निरीक्षण तथा अचानक दौरे करते हैं, ताकि उचित दर की दुकानों के जरिये सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं का उपयुक्त वितरण सुनिश्चित किया जा सके। केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से यह भी अनुरोध किया है कि वे उपभोक्ताओं, विशेषकर महिलाओं के प्रतिनिधियों, स्वैच्छिक तथा उपभोक्ता संगठनों को शामिल करके उचित दर की दुकानों/ग्राम स्तर सहित विभिन्न स्तरों पर सतर्कता समितियां गठित करें ।

PDS in Tamil Nadu

1195. SHRI TINDIVANAM G. VENKATRAMAN: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) what are general norms followed for issuing of ration cards to individuals;

(b) whether the centre insists on the States to have common norms as followed by the Centre;

(c) whether Government are aware that the Public Distribution System in Tamil Nadu is not working properly;

(d) whether it is a fact that Palmolien oil is not being distributed to Tamil Nadu as per original norms set in the past;

(e) whether Government have permitted to State to import Palmolien from abroad; and

(f) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI KAMALUDDIN AHMED) : (a) and (b) The implementation of the Public Distribution System including decisions regarding scales of entitlement of rationed articles and criteria of issue of ration cards to individuals is done by the State Governments and UT Administrations. The Central Government has advised State Governments/U T Administrations to cover all the people in both rural and urban areas by issue of ration cards.

(c) The Central Government has not received any report from the State Government or other agencies regarding malfunctioning of the Public Distribution System as a whole in Tamil Nadu.

(d) to (f) The Central Government has permitted Tamil Nadu Government to import 18,000 MTs of edible oil upto March, 1992. Hence no allocation from Central pool has been made to that State during January/February, 1992.

Super Bazar and Mother Dairy supplying vegetables etc.

1196. SHRI B. K. HARIPRASAD : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Super Bazar and Mother Dairy have